कानपुर, बुधवार, 6 मई, 2026
वर्ष: 03, अंक: 112, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड बंगाल में 'सिंघम' अजय पाल शर्मा की एंट्री...>Pg12

कानपुर को जाम से निजात का मेगा प्लान...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सुलगती आग

कत्ल, आगजनी और दहशत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कई जिलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है।

हिंसा की घटनाएं कोलकाता, हावड़ा, बीरभूम, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, आसनसोल, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों से सामने आई हैं। हावड़ा के उदयनारायणपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि बीरभूम के नानूर में टीएमसी समर्थक की धारदार हथियार से हत्या की गई। कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता मृत पाया गया। इसके अलावा न्यू टाउन, कूचबिहार और आसनसोल में पार्टी कार्यालयों पर हमले और झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा में भी कई जगहों पर मारपीट, धमकी और घरों पर हमलों की खबरें हैं।

अब तक उपलब्ध खबर के अनुसार पोस्ट-पोल हिंसा में कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में भाजपा और टीएमसी दोनों दलों के कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा दर्जनों लोग

- नतीजों के बाद भड़की राजनीतिक हिंसा, 4 मौतें, दर्जनों घायल
- कई जिलों में हमले, आगजनी के बाद सख्त कार्रवाई जारी

घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती 24 घंटों में ही हिंसा का स्तर इतना बढ़ गया कि प्रशासन को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

राज्य के कई हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई पार्टी कार्यालयों को आग के हवाले किया गया, जबकि दक्षिण 24 परगना में दुकानों को जलाने की घटना सामने आई है। कूचबिहार और हावड़ा में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी घरों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि आगजनी की कुल घटनाओं का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स इसे व्यापक स्तर पर फैली हिंसा बता रही हैं।

हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हावड़ा हत्या मामले में कम से कम 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राज्यभर में दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। चुनाव आयोग ने सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई और दोषियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है।

हिंसा को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। टीएमसी ने भाजपा पर अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने टीएमसी पर चुनाव जीत के बाद राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। वहीं भाजपा नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है।

प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का यह दौर राज्य की राजनीतिक संस्कृति पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक ओर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न हुए, वहीं नतीजों के बाद हिंसा ने कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है। मौतों, आगजनी और टकराव की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब भी टकराव का रूप ले रही है। आने वाले दिनों में प्रशासन की सख्ती और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी ही तय करेगी कि राज्य कितनी जल्दी सामान्य स्थिति में लौट पाता है।

क्या प्रशासनिक तैयारी रही कमजोर?

विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहती है, लेकिन नतीजों के बाद कई बार सुरक्षा ढीली पड़ जाती है। यही कारण है कि परिणाम घोषित होते ही हिंसा भड़कती है। इस बार भी शुरुआती घंटों में हालात बिगड़ने से प्रशासन पर सवाल उठे हैं।

क्यों भड़कती है बंगाल में पोस्ट-पोल हिंसा?

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है। राज्य की राजनीति लंबे समय से कैडर आधारित रही है, जहां जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव होता है। सत्ता परिवर्तन या जीत-हार के बाद स्थानीय स्तर पर बदले की भावना हिंसा का रूप ले लेती है।

आगे क्या थमेगी हिंसा?

स्थिति को देखते हुए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं। अगर प्रशासन सख्ती बनाए रखता है और राजनीतिक दल संयम बरतते हैं, तो हालात धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अगर आरोप-प्रत्यारोप और बदले की राजनीति जारी रही, तो हिंसा का यह सिलसिला लंबा खिंच सकता है।

राजनीतिक दलों की भूमिका कितनी अहम?

दोनों प्रमुख दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रखें। नेताओं के बयानों और रणनीतियों का सीधा असर जमीनी कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। अगर राजनीतिक नेतृत्व सख्ती दिखाए, तो हिंसा काफी हद तक रोकी जा सकती है।

बीएसएफ मुख्यालय निशाने पर, 3 घंटे में दो ब्लास्ट

पंजाब में धमाकों का 'डबल अटैक'

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जालंधर। पंजाब में मंगलवार देर रात सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई, जब जालंधर और अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के मुख्यालयों के बाहर महज तीन घंटे के भीतर दो जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी है और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। दोनों घटनास्थलों को तत्काल सील कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम जालंधर पहुंचकर जांच में जुटने वाली है।

- स्कूटी और ग्रेनेड से हमले की आशंका, एनआईए जांच में जुटी
- 18 महीनों में 16 हमलों के बाद पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था फिर कठघरे में

पहला धमाका रात करीब 8:15 बजे जालंधर में हुआ, जहां बीएसएफ मुख्यालय के बाहर खड़ी एक स्कूटी में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की दीवारें हिल गईं और आवाज करीब डेढ़ किलोमीटर दूर तक सुनी गई। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने स्कूटी चालक को हिरासत में लेकर

उससे पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह साजिश थी या लापरवाही।

इस घटना के करीब ढाई घंटे बाद दूसरा धमाका अमृतसर के भारत-पाकिस्तान सीमा के पास खासा क्षेत्र में रात 10:50 बजे हुआ। प्रारंभिक जांच के अनुसार, बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने विस्फोटक को हवा में उछालकर बीएसएफ मुख्यालय की ओर फेंका, जो दीवार से टकराते ही फट गया। धमाके से चारदीवारी के पास बना टीन शेड ढह गया और गेट नंबर 6 और 7 के बीच की दीवार को नुकसान पहुंचा।

घटनाओं की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। शुरुआती तौर पर इसे ग्रेनेड हमला माना जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। आसपास के इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।

गौरतलब है कि पिछले 18 महीनों में पंजाब में करीब 16 पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले हो चुके हैं। ऐसे में बीएसएफ जैसे संवेदनशील ठिकानों पर हुए ये हमले सुरक्षा तंत्र की गंभीर खामियों की ओर इशारा करते हैं। फिलहाल एनआईए और पंजाब पुलिस मिलकर पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने में जुटी हैं।

मातृभूमि का ऋण चुकाने लौटे जॉइंट कमिश्नर

पुश्तैनी घर को बना दिया ज्ञान का मंदिर

अनूप अवस्थी, स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। कहते हैं कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, उसकी मातृभूमि की मिट्टी उसे बार-बार अपनी ओर खींचती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुंबई में इनकम टैक्स विभाग में जॉइंट कमिश्नर पद पर तैनात अंकित तिवारी ने। ऊंचे पद और महानगरीय जीवन के बीच भी उनका मन अपने पैतृक गांव जलीहापुर की गलियों और वहां के बच्चों के भविष्य के लिए धड़कता रहा। इसी भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है।

» मुंबई में इनकम टैक्स विभाग में जॉइंट कमिश्नर पद पर तैनात अंकित तिवारी ने गांव जलीहापुर में खोला आधुनिक विद्यालय, ग्रामीण बच्चों को मिल रही डिजिटल शिक्षा

कानपुर देहात जिले के झींझक विकासखंड में नहर के किनारे जलिहापुर गांव स्थित है यहां पर अच्छी शिक्षा और अन्य संसाधनों का अभाव रहता था.

अंकित तिवारी ने अपने पैतृक घर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक शानदार विद्यालय में परिवर्तित कर दिया। ÷उड़ान पब्लिक स्कूल÷ के नाम से संचालित इस विद्यालय में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान और सामाजिक संस्कार दिए जा रहे हैं। गांव के बच्चों को अब शिक्षा के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ रहा है।सोमवार को विद्यालय परिसर में आयोजित भंडारे एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी डेरापुर सर्वेश कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण कर इसकी सराहना की और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि यदि सक्षम लोग अपनी मातृभूमि के लिए इसी तरह आगे आएं तो गांवों की तस्वीर बदल सकती है। वही गौरी हॉस्पिटल नबीपुर के डायरेक्टर डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा कि गांव में शिक्षा के किए गए प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है अगर इसी तरीके से हर सफल व्यक्ति अपने गांव के बारे में सोच तो गांवों में विकास की धारा बह जाए आमतौर पर लोग सफल होने के बाद बड़े बंगलो और महानगरों में शिफ्ट हो जाते हैं गांव की जमीनी बेचकर लेकिन अंकित तिवारी में साबित किया है कि मातृभूमि का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता.

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए प्रवेश खोले गए हैं। विद्यालय में आधुनिक शिक्षण पद्धति, डिजिटल लर्निंग और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि अंकित तिवारी का यह प्रयास केवल एक स्कूल खोलना नहीं, बल्कि गांव के भविष्य को नई दिशा देना है। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि ÷आज के दौर में लोग गांव छोड़ देते हैं, लेकिन अंकित ने गांव को ही आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों और तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है। कंप्यूटर शिक्षा और आधुनिक संसाधनों के कारण बच्चों में सीखने का उत्साह बढ़ा है। क्षेत्र के अभिभावक भी इस पहल की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। एक सफल अधिकारी द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किया गया यह प्रयास अब पूरे क्षेत्र में मिसाल बनता जा रहा है और अन्य लोगों को भी अपने गांव और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे रहा है।

कौन हैं अंकित तिवारी

गांव की मिट्टी से निकलकर मुंबई में बने इनकम टैक्स के संयुक्त आयुक्त

कानपुर देहात के झींझक क्षेत्र स्थित छोटे से गांव जलीहापुर के रहने वाले अंकित तिवारी ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। वर्ष 2015 बैच के आईआरएस अधिकारी अंकित तिवारी वर्तमान में मुंबई में आयकर विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात हैं। अंकित तिवारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव जलीहापुर के सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई शुरू करने वाले अंकित ने आगे की शिक्षा लखनऊ से पूरी की और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई वहीं से की। उन्होंने नौकरी के साथ ही बिना किसी कोचिंग के स्वयं अध्ययन कर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तैयारी की। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने दूसरे प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आईआरएस बनने के बाद उनकी शुरुआती तैनाती सहायक आयुक्त एवं उप आयुक्त आयकर के रूप में कानपुर में रही, जहां उन्होंने अपनी कार्यशैली और ईमानदार छवि से अलग पहचान बनाई। आज गांव का यह बेटा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है।

कानपुर को जाम से निजात का मेगा प्लान

3904 करोड़ से बनेंगे 4 आरओबी और 2 फ्लाईओवर

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और रोजमर्रा के जाम से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3,904 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर शासन को भेजी है। इस योजना में चार रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) और दो बड़े फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है, जिससे शहर के प्रमुख जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक सुचारु करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के तहत गोविंदनगर, मरियमपुर, फजलगंज, नंदलाल चौराहा और चावला मार्केट जैसे व्यस्त क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 4.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर प्रस्तावित है, जिस पर करीब 945.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्त औद्योगिक और बाजार क्षेत्रों को राहत देगा।

इसके अलावा गंगा बैराज से शुक्लागंज तक 7 किलोमीटर लंबा छह लेन एलिवेटेड रोड और रिवरफ्रंट विकसित करने की योजना भी तैयार है, जिसकी लागत लगभग 1,755 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है और तकनीकी बिड भी खोली जा चुकी है, जिससे इसके जल्द शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं।

शहर के अन्य जामग्रस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए टाटमिल चौराहे से घंटाघर रोड के बीच 424 करोड़ रुपये की लागत से नया दो लेन आरओबी प्रस्तावित है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए 817 मीटर लंबा आरओबी बनाया जाएगा, जिससे जूही अंडरपास और अफीमकोठी के बीच लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। पनकी क्षेत्र के लिए भी दो बड़े आरओबी प्रस्तावित हैं। कालपी रोड से पनकी पड़ाव होते हुए गंगागंज-कल्याणपुर तक 1,197 मीटर लंबा फोरलेन आरओबी (305 करोड़ रुपये) और पनकीधाम रेलवे स्टेशन के पास 942 मीटर लंबा दो लेन आरओबी (235 करोड़ रुपये) बनाया जाएगा।

➪ **गोविंदनगर से गंगा बैराज तक एलिवेटेड रोड का खाका तैयार, पनकी-टाटमिल समेत बड़े जाम प्वाइंट होंगे फ्री**

> अधिकांश परियोजनाओं के एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय भेजे जा चुके हैं और कुछ को वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। रेलवे की तकनीकी मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज होने की उम्मीद है, जिससे लाखों लोगों को रोजाना जाम से राहत मिल सकेगी।
>
> **- बीके सेन, मुख्य परियोजना प्रबंधक सेतु निगम**

शहर की लाइफलाइन बनेंगे फ्लाईओवर

गोविंदनगर से चावला मार्केट तक प्रस्तावित फ्लाईओवर औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों की रीढ़ साबित होगा। इससे न केवल यात्रा समय घटेगा, बल्कि ईंधन की बचत और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

एलिवेटेड रोड से बदलेगा गंगा किनारा

गंगा बैराज से शुक्लागंज तक एलिवेटेड रोड और रिवरफ्रंट परियोजना शहर को नई पहचान दे सकती है। यह न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम करेगी, बल्कि पर्यटन और शहरी सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा देगी।

आरओबी नेटवर्क से खत्म होंगे रेलवे जाम

टाटमिल, ट्रांसपोर्ट नगर और पनकी जैसे इलाकों में ब्रबनने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम इतिहास बन सकते हैं। इससे इमरजेंसी सेवाओं और माल ढुलाई दोनों को बड़ी राहत

मिट्टी की गुल्लक में सहेजे सपनों को मिला नया सहारा

➪ **जनता दर्शन में मासूम बचत की कहानी ने भिगो दीं आंखें, डीएम ने थामा नन्हें हाथों का हौसला**

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कलेक्ट्रेट में बुधवार को आयोजित जनता दर्शन उस समय भावुक हो उठा, जब 11 वर्षीय इस्वा खां अपनी मां शन्नो का हाथ थामे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के सामने पहुंची। जाजमऊ निवासी शन्नो घरेलू विवाद की शिकायत लेकर आई थीं, लेकिन बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली बात छोटी बच्ची की मिट्टी की गुल्लक रही।

मां ने बताया कि इस्वा लंबे समय से अपनी गुल्लक में छोटे-छोटे पैसे जमा कर रही थी कभी रिश्तेदारों से मिले रुपये, कभी बचा हुआ जेब खर्च, तो कभी घर के सिक्के। बच्ची का सपना था कि गुल्लक भरने पर वह अपने लिए स्कूल बैग खरीदेगी। लेकिन पारिवारिक विवाद के बीच उसकी गुल्लक भी तोड़ दी गई और उसमें जमा पैसे निकाल लिए गए।

जब डीएम ने इस्वा से पूछा कि वह गुल्लक में क्या रखती थी, तो उसने मासूमियत से कहा मैं रोज थोड़ा-थोड़ा बचाती थी। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। छोटी बहन मरियम फातिमा चुपचाप पास खड़ी रही, दोनों के चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। मामले में कार्रवाई के निर्देश देने के बाद जिलाधिकारी ने बच्चियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें नया मिट्टी का गुल्लक और स्कूल बैग भेंट किया। इतना ही नहीं, बच्चियों के हाथों से ही नए गुल्लक में 1000 रुपये भी डलवाए। जैसे ही इस्वा के हाथ में नई गुल्लक आई, उसकी आंखों में फिर से सपने चमक उठे। डीएम ने उसे बचत की सीख दी। जनता दर्शन में आई इस छोटी-सी कहानी ने हर किसी के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी।

कानपुर किडनी कांड: फरार अफजाल का झूठ टूटा, होटल रजिस्टर बना सबूत

➪ **कोर्ट में शहर न आने का दावा, सत्यम होटल में ठहरने के मिले पुख्ता साक्ष्य**

➪ **25 हजार का इनामी आरोपी अब शिकंजे में, अवैध ट्रांसप्लांट गिरोह की कड़ियां मजबूत**

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के चर्चित किडनी कांड में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी आरोपी अफजाल का झूठ आखिरकार बेनकाब हो गया है। कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दिए गए हलफनामे में उसने दावा किया था कि वह कभी कानपुर नहीं आया, लेकिन पुलिस जांच में यह दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ। कल्याणपुर स्थित सत्यम होटल के रजिस्टर में उसके ठहरने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

प्रशिक्षु आईपीएस डॉ. सुमेध मिलिंद जाधव के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार को होटल पहुंची और रिकॉर्ड खंगाले। जांच में सामने आया कि अफजाल किडनी खरीदने वाली पारुल तोमर और उसके परिजनों के साथ होटल में रुका था। रजिस्टर के अनुसार, पारुल, उसका पति विकास और भाई दिव्यांश भी दो दिनों तक वहीं ठहरे थे, जिससे पूरे नेटवर्क की गतिविधियों की पुष्टि होती है।

गौरतलब है कि 30 मार्च को केशवपुरम स्थित आहूजा हॉस्पिटल में अवैध किडनी खरीद-फरोख्त और ट्रांसप्लांट का बड़ा खुलासा हुआ था।

इस मामले में अस्पताल संचालक डॉ. सुरजीत आहूजा, उनकी पत्नी डॉ. प्रीति आहूजा समेत अब तक 11 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं किडनी लेने वाली पारुल और डोनर आयुष अलग-अलग अस्पतालों में इलाज कराते मिले थे।अब होटल के रजिस्टर से मिले साक्ष्यों ने फरार आरोपी अफजाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पुलिस का मानना है कि यह सबूत कोर्ट में अहम भूमिका निभाएंगे और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की दिशा में भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

स्वराज इंडिया | कानपुर सिटी | 03

कानपुर किडनी कांड का 'गुप्त डॉक्टर' बेनकाब

ओटी टेक्नीशियन निकला

100 करोड़ के खेल का मास्टरमाइंड

घाटमपुर में भीषण टक्कर, एक चूक से पांच वाहन भिड़े, 16 घायल

इको वैन का इंजन बंद होने से बिगड़ा संतुलन, डंपर-ट्रक समेत कई वाहन आपस में टकराए

बारात से लौट रहे लोग बने हादसे का शिकार, तीन घंटे जाम में फंसा रहा हाईवे

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर-सागर हाईवे पर घाटमपुर के पतारा कस्बे में तिलसड़ा मोड़ के पास मंगलवार देर रात करीब पौने तीन बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पांच वाहन आपस में टकरा गए और 16 लोग घायल हो गए। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे हटाने में पुलिस को करीब तीन घंटे का समय लगा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पतारा की ओर से आ रही एक इको वैन तिलसड़ा मोड़ पर चढ़ाई के दौरान अचानक बंद हो गई और ढलान के कारण पीछे की ओर लुढ़कने लगी। इसी दौरान सामने से गिट्टी लादकर आ रहा डंपर मोड़ पर पहुंचा।डंपर चालक ने टक्कर टालने के लिए वाहन मोड़ा, लेकिन हल्की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों पर नियंत्रण बिगड़ गया। तभी पीछे से आ रहा पानी से भरा मिनी ट्रक डंपर से जा टकराया और पलट गया। इसी बीच मौके पर पहुंची दो अन्य इको वैन और एक कार भी इस हादसे की चपेट में आ गईं।

बताया जा रहा है कि पीछे से आ रहे वाहनों में बारात से लौट रहे लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया।हादसे के दौरान राहत कार्य में जुटे पतारा चौकी प्रभारी ललित शर्मा भी घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार, डंपर और मिनी ट्रक के चालक मौके से फरार हो गए हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फुटपाथ 8.5 मीटर, सड़क संकरी, सीएम ग्रिड योजना को लेकर भड़कीं महापौर

» ग्रीन पार्क चौराहे पर पहुंचकर कराई नाप-जोख, कहा किऐसी सड़क से जाम कैसे खत्म होगा?

» नगर आयुक्त से मांगी पूरी कार्ययोजना, फुटपाथों पर कब्जों पर भी जताई नाराजगी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में बन रही सीएम ग्रिड सड़क को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार को महापौर प्रमिला पाण्डेय खुद मौके पर पहुंच गईं। समाचार पत्रों में सड़क की चौड़ाई कम और फुटपाथ की चौड़ाई अधिक होने की प्रकाशित खबरों तथा जनता के विरोध के बाद महापौर ने अभियंत्रण विभाग की टीम के साथ ग्रीन पार्क चौराहे का स्थलीय निरीक्षण किया। पूर्वान्ह करीब 10:30 बजे मौके पर पहुंचीं महापौर ने अधिकारियों से फुटपाथ की नाप-जोख कराई। जांच में दोनों ओर फुटपाथ की चौड़ाई लगभग साढ़े आठ मीटर पाई गई, जिस पर महापौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर स्कूल भी स्थित हैं और यदि एक साथ दो स्कूलों की बसें निकल जाएं तो सड़क पर भारी जाम की स्थिति बन सकती है।

महापौर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सड़क की चौड़ाई कम और फुटपाथ इतने चौड़े होंगे तो आखिर लोगों को जाम से राहत कैसे मिलेगी? ऐसी सीएम ग्रिड सड़क बनाने का क्या औचित्य है, जब आम जनता को परेशानी ही झेलनी पड़े।निरीक्षण के दौरान महापौर ने यह भी पाया कि आधे से अधिक फुटपाथों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब अभी यह स्थिति है तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे। फुटपाथों को कब्जामुक्त रखने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है, इसका जवाब भी अधिकारियों से मांगा गया।

मौके से ही महापौर ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से मोबाइल पर बातचीत कर सीएम ग्रिड परियोजना की पूरी कार्ययोजना तलब की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की सुविधा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही कार्य होना चाहिए।महापौर के अचानक निरीक्षण से अभियंत्रण विभाग में हड़कंप मचा रहा। स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन को लेकर अपनी शिकायतें महापौर के सामने रखीं।

बंगाल जीत के बाद कानपुर में सांसद का भव्य स्वागत

» हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गूंजे नारे, फूलों की वर्षा और भव्य रोड शो

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर वर्धमान जोन, बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी निभाकर प्रचंड जीत के बाद लौटे सांसद रमेश अवस्थी का बुधवार को कानपुर में ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ। सुबह 9 बजे से ही कार्यकर्ता कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर जुटने लगे और 10 बजे तक हजारों समर्थक ढोल-नगाड़े, शंख और घंटा-घड़ियाल के साथ पहुंच गए।

सुबह 10:30 बजे दिल्ली से आई वंदे भारत ट्रेन से जैसे ही सांसद रमेश अवस्थी बाहर निकले, ÷भारत माता की जय÷, ÷नरेंद्र मोदी जिंदाबाद÷ और ÷रमेश अवस्थी जिंदाबाद÷ के नारों से स्टेशन गूंज उठा। प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी खुली जीप में सवार होते ही कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों कुंतल फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद सैकड़ों वाहनों का काफिला शहर में उत्साह के साथ आगे बढ़ा।स्टेशन से सीधे भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे सांसद अवस्थी का क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। सभा में प्रकाश पाल ने कहा कि यह जीत गंगोत्री से गंगा सागर तक सनातनियों की विजय गाथा है और वर्धमान जोन में 28 में से 22 सीटों पर जीत कानपुर के लिए गर्व का विषय है।सांसद रमेश अवस्थी ने स्वागत से अभिभूत होकर कहा कि यह जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने स्वयं को इस विजय अभियान में ÷गिलहरी÷ की भूमिका निभाने वाला बताया और जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय नेतृत्व तथा बंगाल की जनता को समर्पित किया।इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, विधायक महेश त्रिवेदी, अनूप अवस्थी, कौशल किशोर दीक्षित, विनोद शुक्ला, सुरेश गुप्ता, अवधेश सोनकर, जसविंदर सिंह, प्रमोद विश्वकर्मा, गणेश शुक्ला, विकास दुबे, अमन शुक्ला और अक्षय द्विवेदी सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

गंगोत्री से गंगासागर तक कमल खिला

बंगाल में भाजपा का खेला काम कर गया। ऐसा भी नहीं है कि तीन बार से सत्ता पर काबिज बंगाल की शेरनी ममता से जनता का मोहभंग हाल-फिलहाल की घटना है। भाजपा ने दशकों से आक्रामक रणनीति से चुनावी तैयारी की है। केंद्र सरकार के तमाम संसाधनों का गाहे-बगाहे प्रयोग किया। बंगालियों को रास आने वाले तमाम विमर्श गढ़े और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिये लाखों मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। मोदी-शाह की आक्रामक रणनीति के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ता स्तर पर गहन अभियान चले। फिलहाल, गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा का शासन हो गया है। गंगा के प्रवाह के साथ बहने वाले झारखंड को छोड़ दें तो बाकी राज्य भगवामय हैं। जहां बंगाल में पहली बार कमल खिला है, वहीं तमिलनाडु में थलापति के नाम से चर्चित सुपरस्टार विजय की दमदार एंट्री हुई है। उन्होंने भी परंपरागत राजनीतिक दलों की घोषणाओं से बढ़कर लोकलुभावने वायदे किए हैं। फलतः दो ध्रुवीय द्रविड़ राजनीति सत्ता से बाहर हुई है। स्टालिन न केवल हारे हैं, बल्कि उनकी सरकार भी गई। छह दशक बाद राज्य में गैर द्रविड़ियन सरकार बनने जा रही है। हालांकि, अभी सत्ता में आने के लिये टीवीके को गठबंधन का सहारा लेना होगा। भाजपा के लिये भी पत्ते खेलने के अवसर हैं। जहां बंगाल, केरलम व तमिलनाडु में सत्ता विरोधी लहर में सरकारें धराशायी हुई हैं,वहीं असम में भाजपा की हैट्रिक बनी है। हेमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने भरपूर बहुमत पाया है। पुडुचेरी में फिर एनडीए सत्ता पर काबिज हुआ है। लेकिन भाजपा की इस जीत की खुशी के बीच केरलम में कांग्रेस नीत गठबंधन की वापसी हुई है। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम वाम दलों के लिये दुःस्वप्न ही साबित हुए हैं, केरलम में उनका आखिर गढ़ भी हाथ से निकल गया है। हालांकि, केरलम में भाजपा ने तीन व तमिलनाडु में एक सीट जीतकर हिंदी बेल्ट की पार्टी के ठप्पे से मुक्त होने का प्रयास किया है।इन विधानसभा चुनाव परिणामों का निष्कर्ष यह भी है कि अब क्षेत्रीय क्षत्रपों की मुखर आवाज कुंद हो गई है। जहां ममता,स्टालिन व विजयन सत्ता से बाहर हो गए हैं, वहीं शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक का प्रभाव भी फीका हुआ है। वर्तमान विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश का 72 फीसदी भूभाग व 78 फीसदी आबादी भाजपा शासित है। अनुमान है कि अब भाजपा 'एक देश, एक चुनाव' के मुद्दे पर मुखर हो सकती है। कयास बंगाल को लेकर भी हैं कि वहां आंदोलनों के अगुवा रहे सुवेंदु अधिकारी को सत्ता की बागडोर सौंपी जाएगी, या भाजपा कोई चौंकाने वाली पहल करती है। बहरहाल, बंगाल में भाजपा ने आक्रामक चुनावी रणनीति से महज 8 फीसदी वोट प्रतिशत की वृद्धि से 131 सीटें बढ़ा ली हैं। इतना ही नहीं टीएमसी के मजबूत गढ़ों में 53 सीटें कब्जा ली हैं। बहरहाल, पहले से ही कमजोर विपक्ष को यह परिणाम बड़ा झटका है। कांग्रेस व वाम दलों से किनारा करके चलने की ममता की महत्वाकांक्षी कोशिश का लाभ भाजपा को मिला है।

इस बार उसे केरल की तीन व तमिलनाडु की एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं केरलम में वाम मोर्चे के अंतिम किले का ध्वस्त होना और लगातार टकराव के मूड में रहने वाले स्टालिन की विदाई उसका उत्साह बढ़ाने वाले हैं। बहरहाल- ममता, विजयन और स्टालिन की हार से संकेत मिलता है कि कांग्रेस विपक्ष के कमजोर 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व करती रहेगी। लेकिन भाजपा को आने वाले समय में पंजाब में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, जहां आम आदमी पार्टी व कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के प्रयासों में लगे हैं।

अंतरिक्ष में चीनी-अमेरिकी संघर्ष के बीच भारत

डा0 सुधीर सचदेवा

अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष को लेकर होड़ में दोनों की महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं भारत की भी मानव अंतरिक्ष उड़ानें लॉन्च करने व चंद्रयान मिशन जैसी योजनाएं हैं। आर्टेमिस-टू की सफलता इसमें मददगार होगी। लेकिन यदि दोनों महाशक्तियों के.अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष को लेकर होड़ में दोनों की महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं भारत की भी मानव अंतरिक्ष उड़ानें लॉन्च करने व चंद्रयान मिशन जैसी योजनाएं हैं। आर्टेमिस-टू की सफलता इसमें मददगार होगी। लेकिन यदि दोनों महाशक्तियों के बीच अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ा, तो भारत के लिए चिंताजनक स्थिति होगी। बीते बुधवार को कांग्रेस की एक सुनवाई में अमेरिकी सांसदों को बताया गया,

कि चीन, अमेरिका के लिए 'अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा और प्रतिस्पर्धी' है, जो अपनी खगोलीय क्षमताओं का इस्तेमाल 'कूटनीति और सामरिक प्रभाव के एक हथियार के तौर पर' कर रहा है; यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब चांद पर पहुंचने की इन दोनों देशों की होड़, और तेज़ हो गई है। अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष को लेकर चल रही होड़ में दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले सालों में चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। जहां चीन ने अपनी पहली मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, वहीं अमेरिका के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2028 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर वापस लाना, और 2030 तक वहां एक अंतरिक्ष सैन्य अड्डा बनाना शुरू करना है; इससे इन दोनों महाशक्तियों के बीच कड़ी टक्कर शुरू हो गई है।'सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़' में एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन के हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी ऑन यूरोप की एक सुनवाई में दी जानकारी के मुताबिक, 'जैसे-जैसे देश मानकों के मामले में अमेरिका या चीन में से किसी एक के साथ जुड़ेंगे, तो जीतने वाला देश न सिर्फ़ तकनीक देगा, बल्कि वह उन शर्तों को भी तय करेगा, जिनके आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा। नेटवर्क आपस में काम करेंगे, लेकिन दुनिया को किस नज़र से देखा जाएगासुनवाई के दौरान फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कांग्रेसी रैंडी फाइन के अनुसार, 'जब अंतरिक्ष की बात आती है, तो वह 'चीन को लेकर बहुत चिंतित हैं, जैसा कि मुझे पता है कि और भी कई लोग हैं। मुझे लगता है कि चीन खुद को हमारे साथ युद्ध की स्थिति में देखता है। यह भी कि हम अक्सर इसे उसी नज़र से नहीं देखते।'दरअसल पिछले एक साल में अंतरिक्ष दौड़ में कई अहम घटनाक्रम देखने को मिले हैं; अमेरिका ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम का दूसरा सफल मिशन पूरा किया, वहीं चीन ने अपने 2030 के मून मिशन की तैयारी में कई अहम प्रगति की। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इंसानों को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया है। दूसरी तरफ़ चीन, भारत और पूर्व सोवियत संघ सहित अन्य देशों ने चांद की सतह पर रोबोटिक मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की।गत बुधवार को हुई इस सुनवाई का शीर्षक था, 'ऑर्बिट्स ऑफ़ इन्फ्लुएंस = यूएस स्पेस सिक्योरिटी'। यह सुनवाई उसी दिन हुई, जिस दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्टेमिस-टू के अंतरिक्ष यात्रियों की मेज़बानी की थी। इस कार्यक्रम में नासा मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। सुनवाई के दौरान, एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन का चीन पर आरोप था कि वह ग्लोबल साउथ में अपनी साझेदारियों का विस्तार करके अंतरिक्ष का इस्तेमाल अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कर रहा है।जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्पेस पॉलिसी इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर स्कॉट पेस के मुताबिक, चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को मशहूर 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के ज़रिए आगे बढ़ा रहा है, जिसमें पार्टनर देशों को जोड़ने वाला एक बढ़ता हुआ स्पेस कंपोनेंट भी शामिल है। कैरी बिंगेन के खुलासे के मुताबिक, चीन ने 'ग्लोबल साउथ' कहे जाने वाले लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों के साथ समझौते किए हैं।

एक दौर का चुनाव और अनेक निष्कर्ष विधानसभा हेतु जनादेश

नतीजों से स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक किला स्थायी नहीं। मतदाता अब अधिक सजग और निर्णायक है और चुनाव अब केवल भावनात्मक मुद्दों से नहीं जीते जाते। 2027 के चुनाव इस यथार्थ की पुष्टि करेंगे।हालिया विधानसभा चुनावों ने राजनेताओं को एक बार फिर यह याद दिलाया है कि यहां कोई भी किला स्थायी नहीं होता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत और तृणमूल कांग्रेस की पराजय ने उस धारणा को तोड़ दिया है कि मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व अजेय होता है।

ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ के बावजूद सत्ता परिवर्तन यह बताता है कि मतदाता अब नेतृत्व की छवि से आगे बढ़कर ठोस परिणामों का मूल्यांकन कर रहा है।दक्षिण में तमिलनाडु का परिणाम शायद सबसे दिलचस्प है, जहां अभिनेता विजय की पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट बनना केवल सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि राजनीतिक रिक्तता में नए विकल्प की मांग का प्रमाण है। यह उस बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के बीच मतदाता नए नेतृत्व को परखने के लिए तैयार है। केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति यह दिखाती है कि वैचारिक रूप से सजग माने जाने वाले राज्य भी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं, यदि मतदाता को विकल्प विश्वसनीय लगता है। इसके विपरीत असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत यह साबित करती है कि जहां शासन मॉडल स्वीकार्य है, वहां एंटी-इंकम्बेंसी भी समाप्त हो जाती है। पुदुचेरी में भाजपा गठबंधन की दूसरी बार सरकार इसी निरंतरता का एक और उदाहरण है। इन पांच राज्यों के नतीजों से साफ है कि भारत में अब कोई एक राजनीतिक ट्रेंड नहीं, बल्कि कई समानांतर ट्रेंड चल रहे हैं।इन नतीजों को यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, तो तीन बड़े ट्रेंड सामने आते हैं। पहला है चयनात्मक एंटी-इंकम्बेंसी। यानी हर राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जहां

सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक है, वहां मतदाता उसे दोहराने में संकोच नहीं करता। दूसरा है क्षेत्रीय दलों को चुनौती। यहां बंगाल का परिणाम बताता है कि मजबूत क्षेत्रीय दल भी चुनौती से परे नहीं हैं। और तीसरा है नए विकल्पों की स्वीकार्यता। तमिलनाडु में 'सिने स्टार' से 'सियासी स्टार' बने विजय का उभार यह दर्शाता है कि मतदाता नए चेहरों को मौका देने के लिए तैयार है। इन चुनावों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि भारतीय राजनीति अब एकल नैरेटिव से संचालित नहीं होती। बंगाल में सत्ता परिवर्तन, तमिलनाडु में नए विकल्प का उभार, केरल में वामपंथियों की शिकस्त और कांग्रेस की वापसी तथा असम व पुदुचेरी में स्थिरता- यह विविधता इस बात का संकेत है कि मतदाता अब अधिक सूक्ष्म स्तर पर निर्णय ले रहा है। वह राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन अंतिम फैसला स्थानीय अनुभव और नेतृत्व की विश्वसनीयता के आधार पर करता है।इन संकेतों की असली परीक्षा 2027 में होगी, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। समय-सीमा के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव अगले वर्ष की पहली तिमाही में संभावित हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में वर्ष के अंत में मतदान हो सकता है। लेकिन यह केवल चुनावी कैलेंडर नहीं है। यह उन राजनीतिक प्रवृत्तियों की परीक्षा है, जो अभी उभरकर सामने आई हैं।उत्तर प्रदेश का चुनाव इन सभी ट्रेंड्स का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। यहां का जनादेश केवल राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दिशा भी तय करता है। सामाजिक समीकरण, कल्याणकारी योजनाएं, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे कारक मिलकर यहां चुनावी परिणाम तय करते हैं। बंगाल का उदाहरण दिखाता है कि सत्ता परिवर्तन संभव है, जबकि असम का उदाहरण बताता है कि निरंतरता भी संभव है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह परंपरा जारी रहेगी या मतदाता प्रदर्शन के आधार पर स्थिरता को प्राथमिकता देगा। गुजरात लंबे समय से एक राजनीतिक स्थिरता का उदाहरण रहा है। लेकिन बंगाल के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक गढ़ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यदि विपक्ष संगठित होता है और स्थानीय मुद्दे उभरते हैं, तो यहां भी मुकाबला रोचक हो सकता है।पंजाब में राजनीति हमेशा परिवर्तनशील रही है। यहां 2027 का चुनाव इस सवाल का जवाब देगा कि क्या मतदाता बार-बार बदलाव चाहता है या अब स्थिर शासन की तलाश में है। केरल के नतीजों ने यह संकेत दिया हैं।

नेवादा टोल पर 'फास्ट' टैग बना मजाक, अव्यवस्था में फंसे यात्री

कर्मियों की लापरवाही से लाइन-दर-लाइन भटकते रहे वाहन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। नेवादा टोल प्लाजा पर बदइंतजामी और तकनीकी फेलियर ने यात्रियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। फास्टटैग सिस्टम के ठप पड़ते ही टोल 'फास्ट' नहीं, बल्कि परेशानी का कारण बन गया। बैरियर नहीं खुलने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग जाम में फंसे रहे।

कानपुर से बिल्हौर आ रहे व्यापारी नाजिम और बिल्हौर से शिवराजपुर जा रहे एम.के. ने बताया कि टैग स्कैन होने के बावजूद बैरियर नहीं खुल रहा था। मजबूरन वाहनों को बार-बार रोका गया, जिससे यात्रियों का समय और धैर्य दोनों जवाब देने लगे।

➪ स्कैन हुआ टैग नहीं खुला बैरियर- जाम में जूझते रहे लोग

आरोप है कि हालात संभालने के बजाय टोल कर्मी अव्यवस्था को और बढ़ाते रहे। कभी एक लाइन तो कभी दूसरी लाइन में भेजकर स्थिति को और बिगाड़ दिया गया। नतीजा यह रहा कि कुछ ही देर में टोल प्लाजा जाम का अड्डा बन गया।

खराब प्रबंधन और तकनीकी खामियों के चलते यातायात प्रभावित रहा, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उधर मामले पर टोल प्लाजा प्रबंधक से बात करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

टोल पर स्लो सिस्टम हावी

यात्रियों का कहना है कि जब फास्टटैग जैसी सुविधा भी काम न आए तो टोल देने का औचित्य क्या रह जाता है। तकनीकी खराबी के नाम पर इंतजार कराना और फिर भी कोई स्पष्ट जवाब न मिलना, व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने मांग की है कि ऐसी लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो और सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, ताकि आम लोगों को बार-बार इस परेशानी का सामना न करना पड़े।

सलेमपुर में राशन स्टॉक में गड़बड़ी, 123 कुंतल अनाज का नहीं मिला हिसाब

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील क्षेत्र के ककवन ब्लॉक अंतर्गत सलेमपुर गांव में सरकारी राशन को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 123 कुंतल खाद्यान्न के गायब होने पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, गांव के कोटेदार मोहनलाल का 21 अप्रैल को निधन हो गया था। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलेमपुर की राशन दुकान को अस्थायी तौर पर गढ़वा की दुकान से जोड़ दिया था, ताकि लाभार्थियों को वितरण प्रभावित न हो।इसी बीच पूर्ति विभाग की टीम ने 29 अप्रैल को सलेमपुर स्थित दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अभिलेखों में खाद्यान्न का नियमित उठान दर्ज मिला, लेकिन मौके पर गेहूं, चावल समेत अन्य अनाज का बड़ा हिस्सा गायब पाया गया। कुल मिलाकर करीब 123 कुंतल स्टॉक का मिलान नहीं हो सका, जिससे कालाबाजारी की आशंका जताई गई।

इस पर पूर्ति निरीक्षक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मृतक कोटेदार की पत्नी मंजू देवी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, मंजू देवी का कहना है कि वह केवल वितरण में सहयोग करती थीं। उनके अनुसार, पति की मौत के बाद परिवार के कुछ लोगों ने ही खाद्यान्न में गड़बड़ी की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम के साथ छात्र-शिक्षक सड़कों पर, जनगणना का दिया संदेश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। जनगणना अभियान को सफल बनाने के लिए मंगलवार को नगर में जागरूकता मार्च निकाला गया। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिक्षक और स्कूली छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। छात्रों ने जोश और उत्साह के साथ नारे लगाते हुए लोगों को जनगणना में भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

बिल्हौर इंटर कॉलेज से शुरू हुआ यह मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान जनगणना कराओ, देश को आगे बढ़ाओ जैसे नारों से माहौल जागरूकता से भर गया। राहगीरों और दुकानदारों को भी अभियान के महत्व की जानकारी दी गई। उप जिलाधिकारी बिल्हौर मनीष कुमार ने कहा कि जनगणना से मिलने वाले आंकड़े ही सरकार की योजनाओं का आधार बनते हैं। इसलिए हर नागरिक का दायित्व है कि वह सही और सटीक जानकारी देकर इस प्रक्रिया को सफल बनाए। उन्होंने ऑनलाइन स्व-गणना सुविधा का भी जिक्र करते हुए लोगों से इसका अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।

➪ नारों के जरिए लोगों को किया जागरूक, सहयोग की अपील

➪ अधिकारी बोले -सही आंकड़े ही तय करते हैं विकास की दिशा

तहसीलदार अनुभव चंद्रा, खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार सिंह और बिल्हौर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरजीत यादव सहित कई शिक्षक और कर्मचारी रैली में मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि 2011 के बाद होने वाली यह जनगणना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मार्च के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनगणना में सहभागिता ही क्षेत्र के समग्र विकास की कुंजी है।

नामित सभासदों ने ली शपथ विकास को गति देने का संकल्प

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। नगर पालिका परिषद बिल्हौर में मंगलवार को नामित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। शासन द्वारा हाल ही में मनोनीत सभासदों अनुज अवस्थी, रामनारायण गुप्ता, सुनीता कटिहार, विनीत कुमार और ओमी कुशवाहा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाकर उनके दायित्वों का औपचारिक शुभारंभ कराया गया। कार्यक्रम नगर पालिका परिसर में आयोजित हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही।

मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मिश्रिख सांसद अशोक कुमार तथा एसडीएम मनीष कुमार ने सभी नामित सभासदों को शपथ दिलाई। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि नगर पालिका आम जनता से सीधे जुड़ी संस्था है, इसलिए सभासदों की भूमिका बेहद अहम होती है। उन्होंने सभी से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभासदों को अपने-अपने वार्डों में सक्रिय रहकर जनता से संवाद बनाए रखना होगा और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना होगा।

➪ सांसद अशोक कुमार व एसडीएम ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ

➪ जनसमस्याओं के समाधान और विकास कार्यों पर दिया जोर

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भी नव-नामित सभासदों को बधाई देते हुए उनके कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल, सड़क और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। शपथ ग्रहण के बाद सभी नामित सभासदों ने नगर के विकास के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया।

सभी नामित सभासदों को अध्यक्ष इकलाख खान ने माला पहनकर स्वागत किया। इस दौरान ईओ अंजनी मिश्रा, भाजपा जिला मंत्री जेपी कटियार, विक्रम मिश्रा, सभासद गुड्डा तिवारी, नीतू कुमार, प्रबंध द्विवेदी, चेयरमैन प्रतिनिधि फैजान बेग समेत कई लोग मौजूद रहे।

उन्नाव में बीजेपी विधायकों में टकराव, जमीन विवाद ने पकड़ा तूल

» मोहान विधायक का आरोप स्टे के बावजूद कब्जे की कोशिश, हाथापाई और गाली-गलौज

» सदर विधायक का पलटवार विवाद बहन का, आरोप निराधार; जांच के बाद कार्रवाई की बात

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जमीन विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है।मोहन सीट से विधायक ब्रजेश रावत ने सदर विधायक पंकज गुप्ता और उनकी बहन दीप्ति गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत का कहना है कि कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई और विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज व हाथापाई की गई।

मोहान विधायक की ओर से उनके भाई राजेश रावत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कानपुर-लखनऊ हाईवे पर नवीन मंडी के पास वाजिदपुर उर्फ राजेपुर स्थित करीब छह बीघा जमीन उन्हें ननिहाल से मिली है। आरोप है कि इससे सटी जमीन सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपनी बहन दीप्ति के नाम खरीदी है और उसी के सहारे उनकी जमीन पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है।

मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, जहां से स्टे ऑर्डर भी मिल चुका है।तहरीर के अनुसार, मंगलवार सुबह जानकारी मिली कि विवादित जमीन पर सीमेंट के पिलर गाड़े जा रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर कथित तौर पर मौजूद लोगों ने गाली-गलौज और हाथापाई की। इस संबंध में डीएम और सदर कोतवाली में शिकायत दी गई है।

वहीं, सदर विधायक पंकज गुप्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जमीन विवाद उनकी बहन का है और उन्हें बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है।

उन्होंने हाथापाई और गाली-गलौज की घटना से साफ इनकार किया और कहा कि जिस समय की घटना बताई जा रही है, उस वक्त वह कलेक्ट्रेट में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष नापजोख कर वास्तविक स्वामित्व तय करने की मांग की है।एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह ने बताया कि मामले की तहरीर प्राप्त हो गई है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद के सामने आने के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और प्रशासन पर निष्पक्ष जांच का दबाव बढ़ गया है।

औरैया मेडिकल कॉलेज में धांधली उजागर करने वाले पत्रकार पर दबाव बनाने का आरोप

भगवतीपुर ट्रामा सेंटर, नियम विरुद्ध आदेश और झूठी शिकायतों का मामला गरमाया

भगवतीपुर ट्रामा सेंटर में मनमानी को लेकर डीएम बृजेश कुमार सख्त

औरैया मेडिकल कॉलेज में नियमों की उड़ रही धज्जियां

जनता से सीधा संवाद बना ताकत

जल्द खुल सकता है ट्रामा सेंटर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

औरैया। औरैया मेडिकल कॉलेज में कथित अनियमितताओं और भगवतीपुर ट्रामा सेंटर में कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर लगातार खबरें चलाने वाले पत्रकार ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध आदेशों का खुलासा करने के बाद अब उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आईजीआरएस और पुलिस चौकी के माध्यम से झूठी शिकायतें कर दबाव बनाया जा रहा है।

मामले के अनुसार मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश वीर द्वारा संयुक्त चिकित्सालय की स्टाफ नर्स प्रीति सकवार को ÷मैट्रन÷ नामित करने का आदेश जारी किया गया था। पत्रकार का दावा है कि यह आदेश पूरी तरह नियम विरुद्ध था, क्योंकि मैट्रन का पद राजपत्रित श्रेणी का होता है और किसी स्टाफ नर्स को सीधे इस पद पर नामित नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार पहले सिस्टर पद पर प्रोन्नति आवश्यक होती है, जबकि अस्थायी व्यवस्था में केवल ÷प्रभारी÷ या ÷कार्यवाहक÷ शब्द का प्रयोग किया जाता है।

इस कथित अनियमितता को विभिन्न मीडिया माध्यमों में दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। इसी बीच शासन स्तर से महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के आदेश पर प्रीति सकवार का तबादला भगवतीपुर ट्रामा सेंटर में कर दिया गया, लेकिन आरोप है कि उन्हें जानबूझकर रिलीव नहीं किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी पत्राचार किया गया, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई।

पत्रकार ने आरोप लगाया कि सब डिविजनल आयुक्त चिकित्सालय डॉ. जसवंत रत्नाकर द्वारा रिलीविंग आदेश तैयार कराया गया, लेकिन वास्तविक रूप से कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया, जिससे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बनाए गए भगवतीपुर ट्रामा सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

मामले की शिकायत अधिवक्ता विनोद कुमार द्वारा शासन स्तर तक पहुंचाई गई। पत्रकार ने बताया कि जब उन्होंने जिलाधिकारी से इस विषय पर वार्ता की तो जिलाधिकारी ने ट्रामा सेंटर को शीघ्र सुचारु रूप से संचालित कराने की बात कही थी। इसके बाद खबरें लगातार प्रमुखता से प्रकाशित होती रहीं।पत्रकार का आरोप है कि इन्हीं खुलासों से नाराज होकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र दिलवाया। मेडिकल कॉलेज चौकी से आए फोन कॉल का हवाला देते हुए पत्रकार ने बताया कि चौकी प्रभारी ने स्वयं को मीरा रावत बताया और उनकी पत्नी के संबंध में पूछताछ की, जबकि उनकी पत्नी वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और वर्तमान मामले से उनका कोई संबंध नहीं है।

पत्रकार ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि केवल नियम विरुद्ध आदेशों और प्रशासनिक अनियमितताओं को प्रमाण सहित उजागर किया है। उनका कहना है कि अब भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों का इस्तेमाल कर दबाव बनाने और मीडिया की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, जिलाधिकारी औरैया, पुलिस अधीक्षक औरैया तथा अपर पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। पत्रकार ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि शिकायत झूठी पाई जाए तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

'सूर्य घर' से रोशन होंगे यूपी के स्कूल सोलर ऊर्जा से स्मार्ट क्लास को मिलेगा बल

प्राइमरी स्कूलों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी सरकार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब प्रदेश के स्कूल 'पीएम सूर्य घर योजना' के तहत सौर ऊर्जा से रोशन किए जाएंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र भेजने जा रही है, जिसमें स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अनुमति मांगी जाएगी।

इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलने का प्रावधान है, जिससे स्कूलों को नियमित और सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्राइमरी स्कूल अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली उत्पादन कर सकेंगे।इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास, पंखे और एलईडी लाइट जैसी सुविधाएं बिना रुकावट संचालित हो सकेंगी। खासतौर पर गर्मियों में बच्चों को राहत मिलेगी और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनेगा। साथ ही डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल बिजली खर्च को लेकर कम करेगा, बल्कि स्कूलों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हुए 'आत्मनिर्भर' शिक्षा व्यवस्था की दिशा में भी एक मजबूत पहल साबित होगा।

मानदेय वृद्धि पर शिक्षामित्र सम्मान समारोह, 1754 को मिलेगा लाभ

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के संबोधन का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिक्षामित्रों के मानदेय को 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में इको पार्क, माती में भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने ध्यानपूर्वक देखा।

समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ रसूलाबाद की विधायक पूनम संखवार, भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय तथा मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल उपस्थित रहे। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्र, सभी खंड शिक्षाधिकारी, शिक्षामित्र एवं शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद मंत्री राकेश सचान ने विभागीय स्टालों का अवलोकन कर शिक्षामित्रों का उत्साहवर्धन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में रंग भर दिया। इस दौरान मंत्री, विधायक और जिलाधिकारी ने शिक्षामित्रों को प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया। राकेश सचान ने बताया कि जनपद के 1754 शिक्षामित्रों को बढ़े मानदेय का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। विधायक पूनम संखवार ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने समयबद्ध भुगतान का आश्वासन दिया। समारोह का समापन शिक्षामित्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ हुआ।

सड़क हादसे में घायल मासूम की मौत, गांव में छाया मातम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के थानापुरवा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मंगलवार शाम तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 7 वर्षीय मासूम ऋषभ ने बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

थानापुरवा निवासी राकेश कुमार का बेटा ऋषभ मंगलवार शाम सड़क किनारे खेल रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन-फानन में ऋषभ को कानपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया। हालांकि, सिर और शरीर में आई गंभीर चोटों के चलते बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ऋषभ अपनी तीन बहनों के बीच इकलौता भाई था। बेटे को खोने के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं बहनों का भी दर्द देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने हादसे में शामिल बाइक को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

गंदगी और जलभराव से फैला बुखार, दर्जनों लोग बीमार

स्वास्थ्य टीम ने लगाया शिविर, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। राजपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम जल्लापुर में गंदगी और जलभराव ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ने के कारण बुखार, उल्टी-दस्त जैसी बीमारियां फैल रही हैं। हालात ऐसे हैं कि एक-एक घर में कई लोग बीमार पड़ गए हैं और दर्जनों ग्रामीण निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।

गांव में फैली गंदगी व भरी पड़ी नालियां

करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से जगह-जगह पानी भरा हुआ है। नालियां कीचड़ से पटी हैं और सड़कों पर गंदा पानी जमा है। इसी कारण मच्छर जनित बीमारियों ने तेजी से पैर पसार लिए हैं और बच्चे, युवा व बुजुर्ग सभी इसकी चपेट में हैं।बीमारी फैलने की सूचना पर सोमवार को राजपुर पीएचसी से पहुंची स्वास्थ्य टीम ने गांव में शिविर लगाकर करीब 18 मरीजों का परीक्षण किया और दवाइयां वितरित कीं। इसके बावजूद हालात में खास सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक गांव में एंटी-लार्वा का छिड़काव और जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। गांव के बलबीर, दीपक, रामजनी, शिवपाल कठेरिया, स्नेहा, श्यामलाल, मोहित, आकाश और शिवानी समेत करीब 20 लोग बुखार से पीड़ित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि कई सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।इस संबंध में राजपुर पीएचसी प्रभारी डॉ. सलिल सचान ने बताया कि बुधवार को दोबारा स्वास्थ्य टीम गांव भेजी जाएगी, जो मरीजों का परीक्षण कर उपचार करेगी। समस्या की जानकारी के बावजूद जल निकासी और सफाई व्यवस्था में सुधार न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि जब तक गांव से गंदगी और जलभराव नहीं हटेगा, तब तक बीमारी पर काबू पाना मुश्किल होगा।

हादसे में शहीद पुलिसकर्मियों को नम आंखों से एडीजी ने दी अंतिम विदाई

हरियाणा के नूंह जिले में केएमपी एक्सप्रेस-वे पर हुआ था हादसा

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

जालौन। हरियाणा के नूंह जिले में केएमपी एक्सप्रेस-वे पर 05 मई 2026 को हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीदों का पार्थिव शरीर जालौन पहुंचने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक सलामी दी।

शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक सत्यभान, उपनिरीक्षक मोहित कुमार यादव, आरक्षी प्रदीप कुमार तथा आरक्षी अशोक कुमार शामिल रहे। पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान आलोक सिंह ने अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने शहीदों को कंधा देकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पुलिस लाइन परिसर शोक और गमगीन माहौल में डूबा रहा।

पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है तथा विभाग की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर एवं शोक सलामी दिए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीरों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह जनपदों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।

मुठभेड़ में 4 शातिर गिरफ्तार लूटकांड का खुलासा

पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई, दो बदमाश पैर में गोली

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना राजपुर पुलिस ने मुठभेड़ में चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार कार्रवाई पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन और पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई।

पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की एक सफेद औरा कार में संदिग्ध लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस पर थाना राजपुर पुलिस ने नैनपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया। कार रुकते ही उसमें सवार चालक और उसके पास बैठा व्यक्ति खेतों की ओर भागने लगे, जबकि पीछे बैठे दो व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपने नाम देशराज व अर्पित यादव निवासी ग्राम कौरू, मंगलपुर बताए ।

भाग रहे अन्य दो संदिग्धों का पीछा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इस दौरान थानाध्यक्ष राजपुर बाल-बाल बच गए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। घायल अभियुक्तों ने अपने नाम शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह निवासी ग्राम जरिहा, मंगलपुर व अरुण निवासी तिलक नगर, औरैयाबताए।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, 46,800 रुपये नकदी व जेवराज व घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की औरा कार तथा ताला काटने के औजार (लॉक कटर, छेनी, सब्बल) बरामद किए गए।

पुलिस जांच में सामने आया कि इन अभियुक्तों ने 1/2 मई की रात थाना राजपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति व उसकी मां को रोककर तमंचे के बल पर जेवर लूटे थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त अरुण पर पूर्व में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट व आयुध अधिनियम सहित कई गंभीर मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जबकि अन्य अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष सनत कुमार, उपनिरीक्षक गुरेन्द्र प्रताप सिंह, जितेन्द्र कुमार, विजयपाल सिंह, हेड कांस्टेबल विवेक सिंह, कांस्टेबल गौरव कुमार, सर्वजीत सिंह, शिवप्रकाश व चालक कांस्टेबल विनीत कुमार शामिल रहे।

ऑटो सवार महिला के पर्स से मोबाइल व नगदी पार, दो महिलाओं से पूछताछ

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर कस्बे में पीली कोठी के समीप ऑटो में सवार एक महिला के पर्स से मोबाइल और नगदी चोरी होने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में दो संदिग्ध महिलाओं से पूछताछ की जा रही है।सटटी गांव निवासी नाजमीन मंगलवार सुबह शाहजहांपुर से ऑटो से राजपुर कस्बे आई थीं। ऑटो में पहले से ही दो महिलाएं सवार थीं। इसी दौरान किसी ने उनके पर्स से मोबाइल फोन और करीब 4800 रुपये निकाल लिए। बताया गया कि थाना मार्ग के सामने पहुंचते ही दोनों संदिग्ध महिलाएं ऑटो से उतर गईं। इसके बाद जब नाजमीन ने किराया देने के बाद जब पर्स खोला, तो चोरी की जानकारी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो में सवार रही दोनों महिलाओं तथा शिकायतकर्ता को थाने ले आई। राजपुर थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि ऑटो में सवार दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रही हैं। मामले की जांच की जा रही है।

सपना सिंह ने संभाली खंड शिक्षा अधिकारी की कमान

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा विकासखंड की नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी सपना सिंह ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि विद्यालयों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की पढ़ाई और स्कूलों की व्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान एआरपी वीरेंद्र विक्रम सिंह, अश्वनी कटियार, योगेंद्र त्रिवेदी, कुलदीप सैनी, शिक्षक पीयूष अग्निहोत्री, इंद्रजीत सिंह, संजेश कटियार, रेखा, महेंद्र, कल्पना, जितेंद्र बाबू, प्रमोद, आशीष, अंकित कमल,अर्पित, अरविंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

स्वराज इंडिया की खबर का बड़ा असर

सूखे नलों में आई पानी की धार

» जल निगम के अधिकारियों ने लिया एक्शन

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। स्वराज इंडिया के 2 मई के अंक में हर-घर-नल योजना की खामियों को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और जल निगम (ग्रामीण) को आनन-फानन में मैदान में उतरना पड़ा। जिन गांवों में महीनों से नल सूखे पड़े थे, वहां अब पानी सप्लाई शुरू कर दी गई है।

विकास खंड डेरापुर के मझगवां, बलई खुर्द और मिर्जापुर खुर्द गांवों में योजना सिर्फ कागजों में चल रही थी। ग्रामीण जंग लगे नल, खराब पाइपलाइन और बंद पड़ी सप्लाई से जूझ रहे थे। खबर प्रकाशित होते ही विभाग में हड़कंप मच गया

और खराब वाल्व व अन्य खामियों को दुरुस्त कराने का काम शुरू हुआ। अधिशासी अभियंता टी.आर. कटियार ने जिलाधिकारी कपिल सिंह को भेजी रिपोर्ट में दावा किया है कि अब गांवों में सुबह-शाम पानी दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक था तो खबर छपने के बाद ही सप्लाई क्यों शुरू हुई?ग्रामीणों का कहना है कि पहले सिर्फ कागजी दावे थे, जमीनी हकीकत में पानी नहीं मिलता था।

अब सप्लाई शुरू होने से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों पर पानी का दबाव कम है और व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुई है। यह पूरा मामला साफ करता है कि बिना निगरानी के योजनाएं कैसे लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं। स्वराज इंडिया की खबर के बाद ही विभाग की सक्रियता दिखना कई सवाल खड़े करता है। गांवों में पानी तो पहुंचा, लेकिन लोगों को अब भी डर है कि कहीं यह व्यवस्था फिर से ठप न पड़ जाए।

स्वराज इंडिया

हर-घर-नल योजना में बड़ा खेल!

पाइपलाइन बिछी, नलों पर जंग पानी गायब

3 साल में गिने-चुने दिन ही जलापूर्ति, ग्रामीणों ने उठाए भ्रष्टाचार के सवाल

लोकप्रिय जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की हुई भावभीनी विदाई

जनसेवा, पारदर्शिता और संवेदनशील कार्यशैली के लिए हमेशा याद किए जाएंगे डॉ. दिनेश चंद्र

राहुल अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया

जौनपुर। जनपद के लोकप्रिय एवं कर्मठ जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के स्थानांतरण पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रेक्षागृह में भव्य एवं गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डॉ. दिनेश चंद्र के विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर स्थानांतरण होने के बाद आयोजित इस समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी।

समारोह में कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन के अधिकारी-कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, कलेक्ट्रेट बार संघ के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने पुष्पगुच्छ, स्मृति-चिन्ह और उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया।

उपस्थित लोगों ने उनके सरल स्वभाव, संवेदनशील प्रशासनिक शैली और जनहितकारी कार्यों की जमकर सराहना की। समारोह के दौरान कई अधिकारी भावुक भी दिखाई दिए।

अपने संबोधन में डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा कि किसी भी जिले की सफलता टीम भावना, पारदर्शिता और जनसरोकारों के प्रति संवेदनशीलता से तय होती है। उन्होंने कहा कि जौनपुर में उन्हें अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन का भरपूर सहयोग और स्नेह मिला, जिसे वह जीवनभर नहीं भूल पाएंगे।

अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. दिनेश चंद्र ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण, नियमित जनसुनवाई, निर्वाचन कार्यों के सफल संचालन और लंबित चकबंदी मामलों के समाधान में उल्लेखनीय कार्य किया। पीली नदी के जीर्णोद्धार अभियान को गति देने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना में जनपद को उत्कृष्ट प्रदर्शन की श्रेणी तक पहुंचाया।

इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी विशेष रुचि दिखाई। गौशालाओं में भूसा-चोकर दान अभियान, परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए गुड़-पानी की व्यवस्था और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर उनकी कार्यशैली चर्चा में रही।

विदाई समारोह के अंत में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। जौनपुर प्रशासनिक परिवार ने उन्हें एक संवेदनशील, जनप्रिय और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में याद किया।

इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट लैंडिंग के बाद मची अफरातफरी

» हैदराबाद-चंडीगढ़ फ्लाइट 6ई108 में धमाका, 5 यात्री घायल; केबिन में लगी आग पर क्रू ने पाया काबू

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मोहाली। पंजाब के मोहाली स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब इंडिगो की हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची फ्लाइट (6ई108) में लैंडिंग के तुरंत बाद एक यात्री के पावर बैंक में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके के बाद केबिन के भीतर कुछ देर के लिए आग भी लग गई, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई।

स्थिति को भांपते हुए केबिन क्रू ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशामक यंत्रों से आग पर तुरंत काबू पा लिया।

वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में चार से पांच यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें पास के जीरकपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।इस घटना ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर भी एक अलग तरह की घटना सामने आई थी, जहां रनवे पर बंदरों के झुंड के आ जाने से इंडिगो की एक उड़ान को टेकऑफ से ठीक पहले रोकना पड़ा था।

पायलट की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया, लेकिन उड़ान में देरी और ईंधन की अतिरिक्त खपत हुई।लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा और एयरपोर्ट प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर चिंता बढ़ा दी है। एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

सहारनपुर में रिश्वत लेते अवर अभियंता गिरफ्तार

एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

सहारनपुर। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता नीति के बीच सहारनपुर से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। एंटी करप्शन टीम ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण में तैनात अवर अभियंता आशीष सक्सेना को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी अवर अभियंता के विरुद्ध काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि वह आम नागरिकों के कार्य बिना अवैध धनराशि लिए नहीं करता था। शिकायतकर्ता द्वारा इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी गई, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत लेते समय मौके पर ही पकड़ लिया।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रकरण की शिकायत पूर्व में लोकायुक्त के समक्ष भी की जा चुकी थी,

जिसमें अन्य विभागीय अधिकारियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच में जुट गई हैं, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है।

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है।

लोगों का कहना है कि विकास प्राधिकरण में कार्यों के लिए अवैध वसूली की शिकायतें लंबे समय से मिलती रही हैं। एंटी करप्शन टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, पूरे मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

स्मार्ट मीटर पर पावर कॉरपोरेशन घिरा नियामक आयोग का अल्टीमेटम

बिना सहमति प्रीपेड मीटर पर सख्ती, नियम उल्लंघन पर दूसरा नोटिस जारी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ताओं की सहमति के बिना मीटर को प्रीपेड में बदलने और नए कनेक्शन भी इसी मोड में देने के मामले में नियामक आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। पहले जारी नोटिस का समयसीमा के भीतर जवाब न मिलने पर आयोग ने अब दूसरा नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे की अंतिम मोहलत दी है। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि गुरुवार तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।यह कार्रवाई राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका के आधार पर हुई है, जिसमें पावर कॉरपोरेशन पर विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अधिसूचना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन पर आरोप लगाया है कि वह नियमों को दरकिनार कर उपभोक्ताओं पर जबरन प्रीपेड मीटर थोप रहा है और उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। उन्होंने आयोग से दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।इधर, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद पावर कॉरपोरेशन ने अब तक कोई ठोस कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि नियामक आयोग की सख्ती से आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला संभव माना जा रहा है।

दुष्कर्म का आरोपी 6 घंटे में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। कोतवाली सदर क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 6 घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पवन गौतम के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर विवेक तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली सदर पुलिस व स्वॉट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। घटना 5 मई की रात की है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रामजीवन (निवासी ग्राम रत्तासराय) रवही से सरैंचा जाने वाले मार्ग पर साईफन नहर मोड़ के पास छिपा है और भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ट्रांसफर नीति बनाम अयोध्या नगर निगम

अफसर हटेंगे या शासनादेश फिर टेक देगा घुटने?

स्वराज इंडिया एक्सक्लूसिव

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

चार से आठ साल से जमे अफसरों पर मेहरबानी क्यों? योगी सरकार की तबादला नीति पर उठे बड़े सवाल

अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई तबादला नीति जारी कर साफ संदेश दिया कि तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही जगह जमे अफसरों को हटाया जाएगा, ताकि विभागों में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार की जड़ें न फैलें। लेकिन अयोध्या नगर निगम में हालात ऐसे हैं मानो शासनादेश यहां पहुंचते ही दम तोड़ देता हो। नगर निगम में कई अधिकारी चार से लेकर आठ वर्षों तक एक ही कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार भी ट्रांसफर नीति फाइलों में दम तोड़ देगी या फिर शासन वास्तव में कार्रवाई करेगा?

नगर निगम में वर्षों से जमे अफसरों की सूची

अधिकारी का नाम	पद	एक ही स्थान पर कार्यकाल
गुरूप्रसाद पांडेय	सहायक नगर आयुक्त	4 वर्ष से अधिक
राकेश कुमार सिंह	सहायक लेखा अधिकारी	लगभग 8 वर्ष
राजपति यादव	सहायक अभियंता (सिविल)	4 वर्ष
अन्नू जायसवाल	अवर अभियंता	8 वर्ष
शशिकला चौधरी	अवर अभियंता	4 वर्ष

सूत्रों के मुताबिक वर्षों से जमे इन अधिकारियों ने टेंडर, बिल पासिंग, निर्माण कार्यों और सफाई व्यवस्था तक में ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया है कि बिना सेटिंग के फाइलें आगे नहीं बढ़तीं।

नगर निगम के भीतर अब प्रशासन कम और स्थायी साम्राज्य ज्यादा दिखाई देता है। कर्मचारियों का दावा है कि कई अफसर स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के दम पर हर ट्रांसफर सूची से बच निकलते हैं। यही वजह है कि शासनादेश हर साल आता है, लेकिन कुर्सियां वही रहती हैं। अब निगाहें शासन पर टिकी हैं। क्या रामनगरी में जमे इन अफसरों पर कार्रवाई होगी या फिर एक बार शासनादेश ही नगर निगम की चौखट पर घुटने टेक देगा?

रामनगरी आते वक्त एनएच-27 पर मौत का तांडव !

श्रद्धालुओं से भरी लग्जरी बस बेकाबू होकर गड्ढे में घुसी, दो की दर्दनाक मौत

» सड़क पार कर रहे लोगों को रौंदते हुए पलटी बस, इलाके में मचा हड़कंप

» तमिलनाडु से आए श्रद्धालु सुरक्षित, घायल को जिला अस्पताल रेफर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या आ रही श्रद्धालुओं से भरी एक लग्जरी बस मंगलवार दोपहर एनएच -27 पर रौजागांव के पास बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई।

तेज रफ्तार बस सड़क पार कर रहे लोगों को कुचलते हुए अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में जा घुसी। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के मुताबिक बस लखनऊ से अयोध्या की तरफ आ रही थी और उसमें तमिलनाडु के श्रद्धालु सवार थे। हादसे में पटरंगा थाना क्षेत्र निवासी राजकुमारी (55) और राम सजीवन (58) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि बस सड़क किनारे लोगों को टक्कर मारते हुए सीधे गड्ढे में जा धंसी।

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हाइड्रा मशीन की मदद से बस को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। दोपहर करीब एक बजे हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है।

डीजे की धुन में दौड़ रही थी मौत, आधी रात दुकान में घुसी बेकाबू डीसीएम

» दर्शन नगर में चीखों से टूटी लोगों की नींद, तीन लोग गंभीर घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। दर्शन नगर बाजार में सोमवार आधी रात सड़क पर डीजे नहीं, मौत दौड़ रही थी। फैजाबाद से अकबरपुर की ओर जा रही हैप्पी टांडा डीजे लदी डीसीएम अचानक बेकाबू हुई और सीधे एक दुकान में जा घुसी। रात करीब एक बजे हुए इस हादसे ने पूरे इलाके की नींद और सन्नाटा दोनों तोड़ दिए।टक्कर इतनी भीषण थी कि दुकान का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाहर निकालकर ट्रामा सेंटर पहुंचाया। वाहन संख्या यूपी 45 एफ 1067 बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डीसीएम तेज रफ्तार में थी और चालक नियंत्रण खो बैठा। सवाल यह है कि आखिर सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे ऐसे वाहनों पर लगाम कब लगेगी? पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

नजूल की जमीन को 'पुश्तैनी जायदाद' बनाकर बेचने में एफआईआर

22 लोगों को बेची गई सरकारी जमीन, अब प्रशासन ने खोला फर्जीवाड़े का पूरा चिट्ठा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में नजूल जमीन घोटाले पर आखिरकार प्रशासन की नींद टूट गई। थाना राम जन्मभूमि में ताज मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह कार्रवाई सर्वे नायब तहसीलदार सदर अयोध्या की तहरीर पर की गई है।

जानकारी के मुताबिक खाता संख्या 339 की करीब 6-12-5 क्षेत्रफल वाली सरकारी नजूल भूमि को ताज मोहम्मद ने अपनी ÷पुश्तैनी जमीन÷ बताकर लगभग 22 लोगों को बेच डाला। इतना ही नहीं, जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया। यानी सरकारी जमीन को ऐसे बांटा गया, जैसे कोई निजी विरासत हो।

3 मई 2026 को दर्ज हुई एफआईआर के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े खेल के दौरान जिम्मेदार विभाग आंख बंद करके क्यों बैठा रहा? बिना संरक्षण के क्या सरकारी जमीन का यह कारोबार संभव था? फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

क्या अयोध्या पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' को ठेंगा दिखा रही है?

» महीने भर बाद दर्ज हुई एफआईआर, लेकिन आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहा!

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में कानून का राज चल रहा है या रसूखदारों का संरक्षण तंत्र? यह सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में घटना के महीने भर बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ऐसा तब हुआ जब मामला सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप तक पहुंचा।

मृतक अभिषेक सिन्हा के पिता शरद कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके 19 वर्षीय बेटे को 17 फरवरी 2026 की रात कैफू नामक युवक घर से घुमाने के बहाने ले गया और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। आरोप है कि इसे सड़क हादसा बताकर हत्या को दबाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मोटरसाइकिल पर कथित एक्सीडेंट÷ हुआ, उसमें आरोपी को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन युवक की जान चली गई। आखिर यह कैसा हादसा था?

..लेकिन पुलिस तब भी सोती रही!

परिजनों के मुताबिक आरोपी पहले भी दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दे चुका था। 112 नंबर पर शिकायत भी हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उसी समय कार्रवाई हो जाती तो शायद एक घर का चिराग आज बुझता नहीं। अब पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस शुरुआत से ही मामले को दबाने में लगी रही। पहले तहरीर को इधर-उधर घुमाया गया, फिर समझौते का दबाव बनाया गया। सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर एक शोकाकुल पिता को न्याय की जगह ÷सुलह÷ का पाठ पढ़ाया जा रहा था?

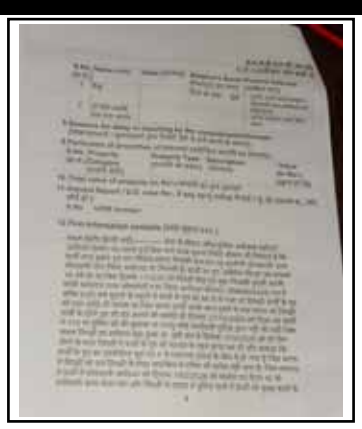

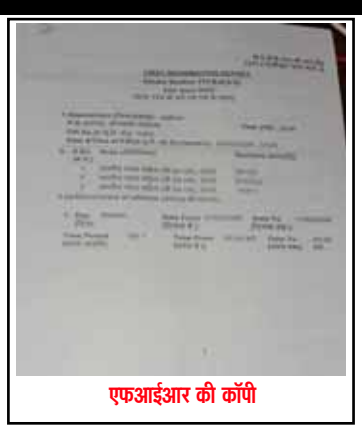

एफआईआर की कॉपी

एसएसपी के दखल पर एफआईआर

सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद जैसे-तैसे एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन महीने भर बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या अयोध्या पुलिस आरोपी को बचाने में लगी है? या फिर दबंग और पैसे वाले लोगों के लिए कानून का अलग संस्करण लागू होता है?

अगर हत्या जैसे गंभीर आरोप में नामजद आरोपी खुलेआम घूमता रहे और पुलिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति करती रहे, तो फिर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का क्या मतलब रह जाता है?

वैश्विक सुरक्षा पर गहराया संकट

हमलों से नहीं थमा ईरान का न्यूक्लियर अभियान

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। अमेरिका और इजरायल के लगातार सैन्य हमलों के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के ताजा आकलन के अनुसार, बीते एक वर्ष में तेहरान की न्यूक्लियर क्षमता लगभग यथावत बनी हुई है। जून 2025 में अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कम से कम एक वर्ष पीछे चला जाएगा, लेकिन वर्तमान रिपोर्टें इस धारणा को कमजोर करती हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ईरान की वास्तविक ताकत उसके पास मौजूद अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (एचईयू) का विशाल भंडार है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी आईएईए के अनुसार, लगभग 440 किलोग्राम 60 प्रतिशत समृद्ध यूरेनियम का पूरा हिसाब अब तक नहीं लगाया जा सका है। आशंका जताई जा रही है कि इसका बड़ा हिस्सा भूमिगत सुरंगों में सुरक्षित रखा गया है। यदि इसे और अधिक समृद्ध किया जाए तो यह कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है।

अमेरिका ने अपने सैन्य अभियानों 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' और 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' को ईरान के रक्षा ढांचे के लिए बड़ा झटका बताया है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इन हमलों से ईरान की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचा, लेकिन परमाणु ढांचे पर इसका प्रभाव सीमित रहा। अमेरिकी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि वह ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा।

इस बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता तनाव स्थिति को और जटिल बना रहा है। ईरान द्वारा इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नियंत्रण सख्त किए जाने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का आवागमन इसी मार्ग से होता है, जिससे ऊर्जा संकट की आशंका गहराने लगी है। 7 अप्रैल को हुए युद्धविराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू हुई है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब भी गतिरोध कायम है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक माध्यमों से यह सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके।

दूसरी ओर, इजरायल द्वारा ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाए जाने से तकनीकी क्षमता पर कुछ असर अवश्य पड़ा है, लेकिन कार्यक्रम पूरी तरह बाधित नहीं हुआ है। ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, हालांकि पश्चिमी देश इस पर संदेह बनाए हुए हैं।

कुल मिलाकर, सैन्य दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। आने वाले समय में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है।

क्यों विफल रहे सैन्य हमले: सैन्य हमलों का असर सीमित इसलिए रहा क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को भूमिगत और सुरक्षित संरचनाओं में विकसित किया है, जिससे उन्हें पूरी तरह नष्ट करना कठिन हो गया है।

कूटनीति बनाम सैन्य विकल्प: अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक प्रयासों पर भी जोर दे रहा है, क्योंकि केवल हमलों से दीर्घकालिक समाधान संभव नहीं दिख रहा।

आगे की चुनौती: ईरान का परमाणु कार्यक्रम न केवल पश्चिम एशिया बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है, जिससे आने वाले समय में बड़े भू-राजनीतिक टकराव की आशंका बनी रहेगी।

सैटेलाइट फोटो

➪ अमेरिकी आकलन में बरकरार रही परमाणु क्षमता, होर्मुज तनाव से ऊर्जा बाजार में बढ़ी बेचैनी

यूरेनियम भंडार की भूमिका

60 प्रतिशत तक समृद्ध यूरेनियम का बड़ा भंडार ईरान को 'ब्रेकआउट क्षमता' देता है, यानी कम समय में हथियार-ग्रेड स्तर तक पहुंचने की संभावना।

होर्मुज का वैश्विक महत्व

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है। यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजार में तेल कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है।

होर्मुज में बढ़ा संकट, 22,000 से ज्यादा अमेरिकी मरीन फंसे

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच फारस की खाड़ी से चिंताजनक खबर सामने आई है। होर्मुज जलडमरूमध्य में आवागमन बाधित होने के कारण 22,000 से अधिक अमेरिकी मरीन सैनिक खाड़ी में फंस गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, ईरान द्वारा इस रणनीतिक मार्ग पर नियंत्रण कड़ा किए जाने से नौसैनिक आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके चलते अमेरिकी बलों की वापसी और रसद आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा हालात में सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने स्पष्ट किया है कि तनाव और छिटपुट हमलों के बावजूद युद्धविराम अभी भी लागू है। उन्होंने बताया कि ईरान ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की घोषणा के बाद अमेरिकी ठिकानों पर 10 से अधिक हमले किए हैं, हालांकि इन्हें पूर्ण युद्ध से नीचे की कार्रवाई माना जा रहा है। संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने होर्मुज के दक्षिणी हिस्से में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार किया है। 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत थल, जल और वायु सेना मिलकर इस क्षेत्र में तैनात हैं, ताकि व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित रखा जा सके और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर कम किया जा सके।

माफिया और गुंडाराज पर नकेल कसने की रणनीति शुरू

बंगाल में 'सिंघम' अजय पाल शर्मा की एंट्री

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के चर्चित और सख्त छवि वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को प्रतिनियुक्ति पर पश्चिम बंगाल भेजा गया है, जहां वे अगले पांच वर्षों तक तैनात रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि बंगाल में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र गंभीर रणनीति पर काम कर रहा है।

अजय पाल शर्मा वही अधिकारी हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान खुले मंच से गुंडों और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी थी।

विशेष रूप से जहांगीर खान जैसे स्थानीय दबंगों के खिलाफ उनके सख्त बयान ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी थी। अब उन्हें उसी राज्य में बड़ी जिम्मेदारी देकर यह संकेत दिया गया है कि सरकार अपराध और दबंगई के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल में माफिया नेटवर्क, संगठित अपराध और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों पर कार्रवाई का जिम्मा दिया गया है। उनकी कार्यशैली तेज, आक्रामक और परिणाम देने वाली मानी जाती है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में कानून का राज मजबूत होगा।

कुल मिलाकर, अजय पाल शर्मा की तैनाती केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संदेश के रूप में देखी जा रही है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि बंगाल में 'सिंघम मॉडल' कितना असरदार साबित होता है।

➪ कानून-व्यवस्था सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी

➪ चुनावी सख्ती के बाद गृह मंत्रालय से मिला इनाम

क्यों चुने गए अजय पाल शर्मा?

अजय पाल शर्मा की पहचान एक 'नो-नॉनसेंस' अफसर के रूप में रही है। उन्होंने यूपी में कई बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा है। उनकी सख्ती और साफ संदेश देने की शैली उन्हें इस मिशन के लिए उपयुक्त बनाती है।

बंगाल में क्या है चुनौती?

पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, स्थानीय माफिया और चुनावी दबाव की समस्याओं से जूझता रहा है। यहां अपराध केवल कानून का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा रहता है।

केंद्र की रणनीति क्या संकेत देती है?

गृह मंत्रालय का यह फैसला साफ करता है कि केंद्र सरकार बंगाल में कानून-व्यवस्था को लेकर सीधा हस्तक्षेप करने के मूड में है। मजबूत अफसर की तैनाती इसी दिशा में एक बड़ा संकेत है।

आगे क्या असर होगा?

यदि अजय पाल शर्मा अपनी छवि के अनुरूप काम करते हैं, तो बंगाल में अपराधियों के मन में डर और आम जनता में भरोसा बढ़ सकता है। हालांकि, राजनीतिक टकराव और स्थानीय विरोध भी सामने आ सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com